

पंजिका.6/6/कॉटेक्ट/टीचर/2024/

दिनांक 27 जुलाई, 2024

विषय:- निर्धारित मानदेय पर, बांछित संख्या में आउटसोर्स शिक्षकों की तैनाती के द्वारा छावनी परिषद चकराता के विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

कैंट बोर्ड चकराता के विभिन्न विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से सरकारी ई-मार्केट पोर्टल यानी <https://gem.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-


### 1. निविदा का विवरण

कार्य का विवरण	निर्धारित मानदेय पर, बांछित संख्या में आउटसोर्स शिक्षकों की तैनाती के द्वारा छावनी परिषद चकराता के विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।
संविदा का अनुमानित बजट	रुपये 48,00,000/-
संविदा की अवधि	1 वर्ष
निविदा शुल्क	रुपए 5900.00/- छावनी मॉड्यूल के माध्यम से। भारत सरकार के नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट अनुमत है।
बयाना धनराशि	रुपये 1,00,000 /- ई-छावनी मॉड्यूल के माध्यम से। समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट अनुमत है।
बोली प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि एवं समय	19-08-2024 (समय जी ई एम पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए अनुसार)
निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि एवं समय	19-08-2024 (समय जी ई एम पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए अनुसार)

मुख्य अधिशासी अधिकारी/परिषद का, कार्यों की अनुमानित लागत बढ़ाने/घटाने तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने का अधिकार सुरक्षित है।

अधिक जानकारी <https://gem.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान छावनी परिषद, चकराता के कार्यालय से संपर्क करें। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बोली दस्तावेज में सभी निर्देशों, शर्तों, प्रपत्रों, नियमों और विनिर्देशों, मात्रा के बिल आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ले। निविदाएं केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। इस निविदा में भाग लेने पर बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह निविदा की शर्तों और नियमों को पढ़ व समझ ले। ऑनलाइन निविदा में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी विचलन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट:- सभी अपडेट/शुद्धिपत्र, प्रस्तुतिकरण सरकारी ई-मार्केट पोर्टल यानी <https://gem.gov.in> पर उपलब्ध होंगे। निविदा दस्तावेजों के लिए आप छावनी परिषद की वेबसाइट भी देख सकते हैं:- <https://chakrata.cantt.gov.in>

  
 (आर.एन. मंडल)  
 मुख्य अधिशासी अधिकारी  
 छावनी परिषद, चकराता।

नोट :- यदि अंग्रेजी पाठ संस्करण और हिंदी अनुवाद के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

## 2. पात्रता मानदंड

छावनी परिषद चकराता, ठेकेदारों/फर्मों/एजेंसियों/संगठनों से, निर्धारित मानदेय पर, बांछित संख्या में आउटसोर्स शिक्षकों की तैनाती के द्वारा छावनी परिषद चकराता के विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति हेतु, प्रस्ताव/कोटेशन आमंत्रित करती है। निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा किए जाने वाली फर्म/एजेंसियां/संगठन, निविदा आवेदन /जीईएम में दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बयाना राशि तथा निविदा लागत ई-छावनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छावनी परिषद चकराता में जमा की जाएगी। ई-छावनी के लिए लिंक <https://echhawani.gov.in> है, बोलीदाता प्ले स्टोर से ई-छावनी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बोली लगाने वाली फर्मों को अपनी बोलियों के साथ निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। उचित दस्तावेजों के बिना बोलियां/निविदाएं सीधे अस्वीकृत कर दी जाएंगी। सी.बी.आर. संख्या 05, दिनांक 06-10-2023 के अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क, वर्तमान में, जी.ई.एम. के बराबर यानी 3.85% निर्धारित किया गया है।

## 2.ए. पात्रता मानदंड:

बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना होगा। इस संबंध में बांछित विवरण तथा सहायक दस्तावेज तकनीकी बोली के फॉर्म के साथ जमा किए जाने चाहिए। सभी दस्तावेजों को क्रमांकित करते हुये अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाना होगा।

1. ठेकेदार/एजेंसी के पास, (विगत तीन वर्षों यानि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/छावनी परिषद /नगर निगम या किसी सरकारी विभाग/एजेंसी में जनशक्ति (मैनपावर) प्रदान किए जाने के न्यूनतम रु. 20,00,000/- (रु. बीस लाख) के कार्य का अनुभव होना चाहिए।। अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने पर पर समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अनुभव से छूट अनुमत है।
2. ठेकेदार/एजेंसी का औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में (अर्थात 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में) (किसी एक वर्ष में या तीन वर्षों में मिलाकर) 40 लाख से कम नहीं होना चाहिए, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस संबंध में प्रमाण पत्र या लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में परिलक्षित होना चाहिए। अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने पर समय-समय पर जारी भारत सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार टर्नओवर से छूट अनुमत है।
3. ठेकेदार/एजेंसी द्वारा, अपने मामले में लागू, विभिन्न नियमों और विनियमों जैसे ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी पंजीकरण तथा पैन कार्ड के तहत सभी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. ठेकेदार/एजेंसी को वैध श्रम लाइसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।
5. श्रम विभाग के नियमानुसार, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आउटसोर्स कार्मिक/कर्मचारी 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए।
6. आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन, श्रम विभाग के नियमानुसार, या परिषद द्वारा जैसा निर्धारित किया गया हो, या केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी या परिषद के स्व- विवेक से देय होगा।
7. ठेकेदार/एजेंसी को, आउटसोर्स कार्मिकों /कर्मचारियों को कम से कम 3 महीने का वेतन अग्रिम रूप से प्रदान किए जाने में सक्षम होना चाहिए। इस संबंध में एक घोषणा उस ठेकेदार/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसकी निविदा, परिषद द्वारा स्वीकार कर ली गई हो।
8. ठेकेदार/एजेंसी को यह बताते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ठेकेदार/एजेंसी भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग/किसी भी राज्य सरकार/निजी क्षेत्र की कंपनियों/पीएसयू/बैंकों आदि द्वारा काली सूची में नहीं है/न कभी डाली जा चुकी है।



### 3. नियम और शर्तें

#### 3.1 कार्य का दायरा

निर्धारित मानदेय पर, वांछित संख्या में आउटसोर्स शिक्षकों की तैनाती के द्वारा छावनी परिषद चकराता के विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति।

#### 3.2 संविदा का नाम

निर्धारित मानदेय पर, वांछित संख्या में आउटसोर्स शिक्षकों की तैनाती के द्वारा छावनी परिषद चकराता के विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति।

#### 3.3. संविदा की अवधि

संविदा प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर अगले 4 वर्ष तक अथवा उस अवधि तक जिसके लिए /सीईओ संविदा के विस्तार का निर्णय लेगा, बढ़ाई जाएगी। संविदा की अवधि, बोर्ड द्वारा समाप्त की जा सकती है, बशर्ते कि उस समय व्यक्तियों हेतु छावनी परिषद की वांछितता बरकरार हो अथवा संविदा, अवधि से पहले, कम/ समाप्त की जा सकती है यदि चयनित एजेंसी द्वारा तैनात जनशक्ति की गुणवत्ता घटिया हो अथवा सेवा में कमी हो अथवा कार्य की वांछितता का समापन हो गया हो। छावनी परिषद चकराता अथवा मुख्य अधिशासी अधिकारी का, चयनित एजेंसी को एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय इस प्रारंभिक संविदा को समाप्त कर दिये जाने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 तथा इसके संशोधन के अनुसार प्रदान की जाएगी। अपनी कार्यात्मक वांछितता के आधार पर आउटसोर्स कार्मिकों /कर्मचारियों/आउटसोर्स शिक्षकों की संख्या बढ़ाये /घटाये जाने का छावनी परिषद /मुख्य अधिशासी अधिकारी का अधिकार सुरक्षित है।

#### 3.4. सामान्य नियम और शर्तें

3.4.1. ठेकेदार/एजेंसी का काम निर्धारित मानदेय पर, वांछित संख्या में आउटसोर्स शिक्षकों की तैनाती के द्वारा छावनी परिषद चकराता के विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की आपूर्ति किया जाना होगा। ठेकेदार/एजेंसी का भवन और अन्य बुनियादी ढांचे, फर्नीचर और फिक्स्चर पर कोई अधिकार नहीं होगा, जो छावनी परिषद, चकराता की संपत्ति रहेगी वही इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।

3.4.2 सभी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार आदि के सभी प्रभार/कर जो संविदा पर लागू हों उनका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा रसीद प्रस्तुत किए जाने पर छावनी परिषद द्वारा ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी नए शुल्क/कर का भुगतान बोर्ड द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

- 3.4.3 मासिक भुगतान केवल ठेकेदार द्वारा किए गए संतोषजनक कार्य एवं उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, अनुपस्थित व्यक्तियों की कटौती चालू न्यूनतम मजदूरी/निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर की जाएगी।
- 3.4.4 निविदा दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाने के अलावा, इच्छुक कंपनियों/बोलीदाताओं को 1,00,000/- रुपये की बयाना राशि (ईएमडी) और 5900/- रुपये की निविदा लागत ई-छावनी के माध्यम से छावनी परिषद, चकराता में जमा करनी होगी और इसकी रसीद ऑनलाइन बोली में अपलोड की जानी होगी। ऑनलाइन बोली में प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किए जाने पर संबंधित फर्म/ठेकेदार/बोलीदाता को भारत सरकार के आदेश अनुसार ईएमडी और निविदा लागत के लिए छूट दी जाएगी।
- 3.4.5 सफल बोलीदाता को निविदा अनुमानित राशि/संविदा मूल्य की (5% या अधिक, भारत सरकार के आदेश के अनुसार) या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई दर से प्रतिभूति जमा ई-छावनी मॉड्यूल के माध्यम से छावनी परिषद, चकराता में जमा करनी होगी। प्रतिभूति जमा संविदा समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
- 3.4.6 निविदाएं <https://gem.gov.in> पर प्रकाशित की गई हैं। इच्छुक एजेंसियों/बोलीदाताओं को जी ई एम (सरकारी ई मार्केट) की प्रक्रिया के अनुसार <https://gem.gov.in> पर ऑनलाइन बोली लगाने की सलाह दी जाती है।
- 3.4.7 पहले, निर्धारित तिथि और समय पर, तकनीकी बोली/दस्तावेजों को छावनी परिषद, चकराता के कार्यालय में (जी ई एम पोर्टल में) कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, यदि कोई हो, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहता हो, खोला जाएगा। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन एक तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। केवल मानदंडों के अनुरूप पाये गए, तकनीकी रूप से योग्य, पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ निर्धारित तिथि और समय पर छावनी परिषद चकराता के कार्यालय में (जी ई एम पोर्टल में) छांटे (शॉर्ट-लिस्ट किए) गए ठेकेदारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
- 3.4.8 बोलीदाता तकनीकी और वित्तीय बोली को केवल जी ई एम पोर्टल में ही उद्धृत करेगा।
- 3.4.9 सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 3.4.10 इस संविदा के किसी भी खंड के उल्लंघन के मामले में मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास, ठेकेदार को कोई भी पूर्व सूचना दिये बिना कथित प्रतिभूति जमा को जब्त किए जाने का पूर्ण अधिकार व शक्तियां होंगी तथा इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.4.11. आउटसोर्स कार्मिकों के लिए मांग जारी होने के बाद 7 दिनों के भीतर सेवाएं शुरू न किए जाने पर संविदा के मासिक मूल्य के 1% या उससे अधिक की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा लिखित आवेदन दिये जाने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी को इस देरी को माफ किए जाने, लगाए गए जुर्माने को किसी भी सीमा तक कम या माफ किए जाने की शक्ति होगी, यदि ऐसा किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा दिए गए आधार उचित और संतोषजनक हैं।



- 3.4.12. ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कार्यकर्ता की गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में छावनी बोर्ड, चकराता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार को स्वीकार्य होगा। यदि ठेकेदार द्वारा तैनात आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में कोई कमी पाई जाती है, तो ठेकेदार को बिना कोई अतिरिक्त भुगतान लिए बताई गई कमी को दूर करना होगा। ठेकेदार को लिखित में नोटिस दिये जाने के बाद सेवाओं को अस्वीकार किए जाने या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर अपने स्तर पर ये सेवाएँ करवाने/बदलवाने का अधिकार भी परिषद के पास सुरक्षित रहेगा और इस कारण होने वाले व्यय को, जैसा भी परिषद उचित समझे, ठेकेदार के किसी अन्य आउटसोर्सिंग देयों से या प्रतिभूति/बैंक गारंटी के किसी या सभी भागों को जब्त करके वसूल किया जाएगा।
- 3.4.13. छावनी परिषद चकराता में तैनात किए जाने वाले आउटसोर्स कार्मिकों की संख्या के बारे में ठेकेदार को पर्याप्त पहले सूचित किया जाएगा। ठेकेदार उक्त सेवा प्रदान किए जाने के लिए वांछित कार्मिकों को तैनात करेगा व समय-समय पर तैनात किए या बदले जाने पर व्यक्तियों के नाम, पितृत्व (पेरेंटेज), आवासीय पता, आयु प्रमाण, उनकी नौकरी के वास्ते उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक/तकनीकी योग्यता की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी तुरंत देगा।
- 3.4.14. ठेकेदार के कर्मचारियों की समुचित पहचान के लिए, ठेकेदार स्वयं उन्हें पहचान पत्र/पहचान दस्तावेज जारी करेगा तथा वे ड्यूटी के समय पहचान पत्र प्रदर्शित किए जाने के लिए कर्तव्य-बद्ध होंगे।
- 3.4.15. मुख्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों के कामकाज की कोई भी आकस्मिक जांच किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक संख्या में व्यक्ति तैनात हैं तथा वे अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन कर रहे हैं।
- 3.4.16. उक्त सेवा प्रदान किए जाने का दायित्व ले लिए जाने पर, ठेकेदार, मुख्य अधिशासी अधिकारी के साथ परामर्श करके आउटसोर्स कर्मियों के लिए कार्य-विधि तथा कार्य दिशा-निर्देश तैयार करेगा। ठेकेदार समय-समय पर अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करता रहेगा तथा उक्त व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किए जाने के लिए, यदि कोई वांछित हो, तो अतिरिक्त उपाय करेगा। तथापि, ठेकेदार व साथ ही साथ ड्यूटी पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा सौंपे गए ऐसे किसी भी कार्य (कार्यों) को किए जाने के लिए, उन्हें दिए गए निर्देशों/अनुदेशों का पालन किए जाने हेतु बाध्य होंगे।
- 3.4.17. कार्य के लिए ठेकेदार/एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्ति सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए ठेकेदार/एजेंसी के कर्मचारी होंगे। दूसरे शब्दों में, ठेकेदार/एजेंसी ही संबंधित ठेकेदार/एजेंसी द्वारा तैनात आउटसोर्स कर्मियों/कर्मचारियों का नियोक्ता होगा और छावनी परिषद, चकराता को किसी भी मामले में कर्मचारियों/व्यक्तियों का नियोक्ता नहीं माना जाएगा।
- 3.4.18. ठेकेदार/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से फिट हों।
- 3.4.19. इस प्रकार तैनात व्यक्ति ठेकेदार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे और ठेकेदार उनके वेतन आदि और ऐसी अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जिसका भुगतान किए जाने के लिए ठेकेदार विभिन्न श्रम विनियमन और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत उत्तरदायी है। छावनी परिषद, चकराता अपने स्तर पर ऐसी किसी भी देयता से मुक्त होगी।



- 3.4.20. ठेकेदार/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों, जो भी लागू हों, के तहत स्वीकार्य, देय वेतन और अन्य लाभ मिलें।
- 3.4.21. ठेकेदार/एजेंसी तैनात व्यक्तियों के प्रतिकानून, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पी.एफ. अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, बोनस अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि, यदि लागू होते हों तो, के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा/ होगी। ठेकेदार अपने स्तर पर ईएसआई, ईओएफ, ईडीएलआई में, यदि लागू हो तो, योगदान के लिए, तथा नियमों के अनुसार ऐसे रिकॉर्ड अनुरक्षित रखे जाने हेतु, जिम्मेदार होगा। इस तरह ड्यूटी हेतु तैनात किए गए अपने आउटसोर्स कार्मिकों को ठेकेदार हर महीने की 07 तारीख तक वेतन वितरित किए जाने की व्यवस्था करेगा। भुगतान के लिए बिल जमा किए जाते समय, ठेकेदार को काम पर लगाए हुये सभी कार्मिकों के संबंध में ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी (जैसा लागू हो) या प्रवर्तित अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार के कर जैसी वैधानिक देनदारियों के लिए किए गए पिछले भुगतान का प्रमाण, साथ-साथ तैनात आउटसोर्स कार्मिकों की उपस्थिति रिपोर्ट, जो कि छावनी परिषद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इनका भुगतान छावनी परिषद द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार, तैनात आउटसोर्स कार्मिकों को मानदेय/देयों के भुगतान के संबंध में प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा। उचित प्रपत्र में बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर, परिषद, भुगतान कर देगी। छावनी परिषद, चकराता, तैनात किए गए आउटसोर्स कार्मिकों तथा ठेकेदार के बीच वेतन के वितरण या अन्यथा के संबंध में किसी भी विवाद में शामिल या उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। वांछित होने पर, इस छावनी परिषद में संविदा के आधार पर कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के बारे में श्रम विभाग ईपीएफ, ईएसआई आदि के संबंधित प्राधिकारी को विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किए जाने में किसी भी चूक या देरी के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 3.4.22. यदि ठेकेदार द्वारा तैनात कोई भी व्यक्ति मानकों पर खरा नहीं उतरता या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त रहता है, तो ठेकेदार मुख्य अधिशासी अधिकारी या सीईओ द्वारा इस संबंध में इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी की रिपोर्ट पर ऐसे कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा।
- 3.4.23. यदि सीईओ/परिषद द्वारा ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्तियों के संबंध में कोई शिकायत या दोष बताया जाता है, तो ठेकेदार बिना किसी और तर्क के तुरंत तैनात व्यक्ति को बदल देगा।
- 3.4.24. ठेकेदार/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि तैनात आउटसोर्स कर्मचारी समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित समय-अनुसूची व अवकाश अनुसूची का पालन करें। किसी लंबी अनुपस्थिति यानी 7 दिनों से अधिक की स्थिति में, ठेकेदार अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- 3.4.25. ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में, ठेकेदार/एजेंसी चोरी, लापरवाही (मिस हैंडलिंग) या अन्य किसी तरीके से परिषद की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान तथा किसी भी तरह के दावों की परिषद को क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी। ठेकेदार/एजेंसी बोर्ड की चल/अचल संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की धनराशि की वसूली के भुगतान के लिए



जिम्मेदार होगा/होगी। यदि ठेकेदार/एजेंसी का कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह के विवाद, चाहे जो भी हो, में उलझता है, तो उसका प्रतिवाद संबंधित ठेकेदार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि परिषद को भी एक पक्ष बनाया जाता है और उसे मुकदमा लड़ना पड़ा तो, तो वकील की फीस तथा अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक व्यय की यदि कोई लागत हो, तो बोर्ड द्वारा मांग किए जाने पर ठेकेदार को उसका अग्रिम भुगतान करना होगा। इसके अलावा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के लिए, चाहे जो भी हो, परिषद पर किसी भी तरह का कोई वित्तीय या कोई अन्य कानूनी दायित्व न आये और इस संबंध में वह परिषद की क्षतिपूर्ति करेगा।

3.4.26. परिषद को आगे, इस संविदा के तहत ठेकेदार/एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान से या ठेकेदार/एजेंसी की प्रतिभूति जमा राशि में से किसी भी राशि को समायोजित या पुनर समायोजित या कटौती किए जाने का अधिकार है।

3.4.27. (संविदा अवधि पूरी होने के बाद भी) दोनों पक्ष राशि को समायोजित किए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

3.4.28. यदि ठेकेदार/एजेंसी ने इस प्रकार तैनात आउटसोर्स कार्मिकों में से किसी को वेतन का भुगतान नहीं किया है, तो परिषद को उक्त कर्मचारी के वेतन को पूर्वोक्तानुसार इस संविदा के तहत ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से या ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि में से समायोजित या पुनर समायोजित या कटौती किए जाने का अधिकार होगा।

3.4.29. ड्यूटी के दौरान तैनात किसी भी कर्मचारी की चोट/मृत्यु के कारण किसी भी क्षति/मुआवजे के लिए ठेकेदार/एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा/होगी।

3.4.30. संविदा आधार पर तैनात कर्मचारियों द्वारा सेवाओं में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर या ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा अवज्ञा किए जाने की स्थिति में, मुख्य अधिशासी अधिकारी या सीईओ द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात, जैसा भी उचित समझे, 500/- रुपए तक का जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा मुख्य अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम व ठेकेदार हेतु बाध्यकारी होगा।

3.4.31. ठेकेदार/एजेंसी, अपने द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को मजदूरी का भुगतान किए जाने, व ऐसी मजदूरी हर महीने के 7 वें दिन दिये जाने तथा यह सुनिश्चित किए जाने कि मजदूरी का वितरण उसके दैनिक श्रमिकों/आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया गया है, जिम्मेदार होगा/होगी। नकद भुगतान बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा।

3.4.32. ठेकेदार/एजेंसी उस मजदूरी के लिए जिम्मेदार होगा/होगी जो दैनिक श्रमिकों/आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे जायेगी। छावनी परिषद चकराता का लेखाकार ठेकेदार को बिलों का भुगतान जारी किए जाने से पहले यह जांचने तथा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के लिए अधिकृत है कि वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी यदि कोई हो, जीएसटी आदि अधिकृत खाते में जमा हो गए हैं।

3.4.33. निम्नलिखित में से किसी भी प्रासंगिकता में संविदा को समाप्त किया जा सकता है:

(ए) अनुबंध अवधि की समाप्ति पर।

(बी ), यदि ठेकेदार/एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक तथा सेवाओं हेतु निर्धारित मानदंड और मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती तो सेवाओं की निरंतरता के दौरान किसी भी समय एक महीने के नोटिस पर।

या

(सी ) ठेकेदार द्वारा संविदा के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर।

या

(डी) ठेकेदार द्वारा संविदा या उसके किसी भाग को या उसमें या उसके अधीन किसी लाभ को तीसरे व्यक्ति को सौंपे जाने पर, ताकि संविदा का पूरा या कोई भाग किसी तीसरे व्यक्ति को उप-पट्टे पर दिया जा सके।

(ई) सक्षम न्यायालय द्वारा ठेकेदार/एजेंसी को दिवालिया घोषित किए जाने पर। उपर्युक्त विचारित स्थिति में संविदा की समाप्ति के लिए नोटिस अवधि के दौरान, ठेकेदार/एजेंसी नोटिस अवधि की समाप्ति तक पूर्व की भांति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा/रहेगी। ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आधार पर, चाहे जो भी हो संविदा की समाप्ति पर अपने द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा दे तथा यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड के लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान/बाधा/समस्या उत्पन्न न करे।

3.4.34. ठेकेदार/एजेंसी को छावनी परिषद, चकराता की पूर्व लिखित सहमति एवं अनुमति के बिना इस संविदा के तहत मिले अपने अधिकारों एवं दायित्वों को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित किए जाने, सौंपने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

3.4.35. केवल उन निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिन्हें तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया है।

3.4.36. छावनी परिषद, चकराता का संविदा करने वाली कंपनी को एक माह का नोटिस दिये जाने के पश्चात भी, प्रारंभिक अवधि के दौरान संविदा को समाप्त कर दिये जाने का अधिकार सुरक्षित है।

3.4.37. ठेकेदार/एजेंसी द्वारा, कार्य शुरू होने से पूर्व, छावनी परिषद में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे- आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पते का प्रमाण आदि।

3.4.38. व्यक्तियों के पूर्ण विवरण यानि जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, पता, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, अनुभव आदिकी सूची।

3.4.39. यदि सफल ठेकेदार/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति कोई ऐसी चूक या गलती करता है जो कदाचार/अनुशासनहीनता/अक्षमता/दुराचार/सुरक्षा जोखिम के बराबर है, तो सेवा प्रदाता ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा, जिसमें उनके संज्ञान में लाए जाने के 1 दिन के भीतर दुराचार/सुरक्षा जोखिम होने हेतु पुलिस में मामला दर्ज कराया जाना व उन्हें कार्य स्थल से हटाया जाना शामिल है।

3.4.40. ठेकेदार/एजेंसी, छावनी परिषद में तैनात कार्मिकों को बड़े पहचान पत्र, कार्मिक की नवीनतम फोटो तथा व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि, पदनाम तथा पहचान चिह्न आदि के साथ उपलब्ध कराएगी।



- 3.4.41. ठेकेदार/एजेंसी कार्यालय परिसर में अपने कार्मिकों का उचित आचरण सुनिश्चित करेगा/करेगी तथा मादक पेय, पान, धूम्रपान, आवारागर्दी आदि पर प्रतिबंध प्रवर्तित करेगा/करेगी। सेवा प्रदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्मिक सरकारी कार्यालय के अनुरूप ड्रेस कोड का पालन करें।
- 3.4.42. एजेंसी एक समन्वयक नियुक्त करेगी, जो छावनी परिषद चकराता के साथ बातचीत के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि बिना किसी व्यवधान के इष्टतम सेवाएं प्राप्त की जा सकें।
- 3.4.43. सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, ठेकेदार, छावनी परिषद, चकराता में नियोजित और तैनात कार्मिकों के संबंध में विभिन्न श्रम विधानों के अर्थ में "नियोक्ता" होगा। छावनी परिषद में ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों का छावनी परिषद, चकराता के साथ या विरुद्ध न तो नियोक्ता और कर्मचारी सम्बन्ध होने का कोई दावा होगा, और न ही उनका कोई प्रिन्सिपल व एजेंट का सम्बन्ध होगा।
- 3.4.44. ठेकेदार/एजेंसी तैनात व्यक्तियों से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण/विवादों के समाधान के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। छावनी परिषद, चकराता किसी भी प्रकार से ऐसे मुद्दों के निपटान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 3.4.45. छावनी परिषद चकराता सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा तैनात किसी व्यक्ति को उसके कार्य/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली किसी भी क्षति, हानि, दावे, वित्तीय या अन्य चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, न ही किसी प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।
- 3.4.46. ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति संविदा की अवधि के दौरान या उसके पश्चात छावनी परिषद के आकस्मिक, तदर्थ, नियमित/स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं का दावा नहीं करेंगे और न ही इसके लिए पात्र होंगे।
- 3.4.47. समाप्ति पर या अन्यथा इस संविदा को खत्म कर दिये जाने की स्थिति में, ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति नियमित/अन्य रूप से सेवा में सम्मिलित कर लिए जाने या सेवा में आने के लिए उन्हें कोई भी छुट्टि दिये जाने के न तो पात्र होंगे और न ही उनका कोई दावा होगा।
- 3.4.48. ठेकेदार की मृत्यु, अशक्तता, दिवालिये हो जाने या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों से उत्पन्न होने वालीजरूरत के हालात में, उस (ठेकेदार) के संविदा दायित्वों का वहन निम्नलिखित द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड उचित समझे।
- (i) एकमात्र स्वामी के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी
- (ii) कंपनी या फर्म के मामले में अगला भागीदार। अन्यथा मुख्य अधिशासी अधिकारी का, मामले की परिस्थितियों के अनुसार जैसे भी वह उचित समझे, उसे (मामले को) निपटाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 3.4.49. आउटसोर्स कार्मिकों/कर्मचारियों के संविदा कार्य के संचालन के दौरान उत्पन्न विवाद के संबंध में किसी भी अन्वेषण, पूछताछ के दौरान ठेकेदार/एजेंसी का उनके वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.4.50. इस संविदा से संबंधित सभी विवाद केवल चकराता/विकासनगर/देहरादून/उत्तराखंड न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

- 3.4.51. इस अनुबंध में कोई भी विवाद या मतभेद उत्पन्न होने, या विवाद या मतभेद के इस अनुबंध को छूने, या अनुबंध से संबंधित होने की स्थिति, जो भी हो, में, विवाद या मतभेद को एकमेव मध्यस्थ (पीडीडीई, मध्य कमान, लखनऊ या सीईओ/परिषद द्वारा तय किए गए किसी अन्य अधिकारी) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता, मध्यस्थता-अधिनियम तथा समय-समय पर इस अधिनियम में किए गए संशोधनों से अभिशासित होगी।
- 3.4.52. निविदा प्रक्रिया को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) रद्द/अस्वीकार किए जाने का अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, चकराता द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के तय किया जाएगा।
- 3.4.53. तकनीकी व्यक्तियों की योग्यता, जैसा भी मामला हो, जैसे कि शिक्षक, क्लर्क, अन्य तकनीकी कर्मचारी, एमटीएस कर्मचारी आदि, या तो मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, चकराता/परिषद द्वारा तय की जाएगी या शैक्षिक योग्यता उस स्थायी पद के अनुसार तय होगी जिसके विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जा रहा हो। परिषद/सीईओ के निर्णय के अनुसार, एजेंसी, स्वयं अपने खर्च पर, विज्ञापन प्रकाशित करायेगी जिसकी प्रतिपूर्ति, बिल आदि प्रस्तुत किए जाने पर, की जाएगी तथा नियुक्त किए जाने के लिए एजेंसी छटनी किए गए उम्मीदवारों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराएगी और सीईओ, तकनीकी/गैर तकनीकी/एमटीएस कार्य वांछितताओं के लिए, उन (उम्मेदवारों) की योग्यता के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन करेंगे।
- 3.4.54 ठेकेदार/एजेंसी को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत/निगमित, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए।
- 3.4.55 ठेकेदार/एजेंसी, छावनी परिषद, चकराता में अपने द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा आदि से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार होगा/होगी।
- 3.4.56 ठेकेदार/एजेंसी, छावनी परिषद, चकराता को प्रदान की गई सेवाओं के कारण, सभी करों, लेवी, उपकर आदि को समय-समय पर, मामले के मौजूदा नियमों तथा विनियमों के अनुसार, संबंधित कर संग्रह अधिकारियों को जमा किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगा/होगी।
- 3.4.57 ठेकेदार/एजेंसी, लागू कानूनों के तहत, सभी वैधानिक रजिस्टर अनुरक्षित रखेगी। मांग किए जाने पर, कंपनी, इन्हें (वैधानिक रजिस्टर को), छावनी परिषद के संबंधित प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
- 3.4.58 स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) समय-समय पर संशोधित आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र छावनी परिषद द्वारा कंपनी को प्रदान किया जाएगा।
- 3.4.59 यदि निविदा देने वाली कंपनी, उचित कानून के अंतर्गत, किसी भी वैधानिक/कर, देयता का पालन करने में विफल रहती है तथा इसके परिणामस्वरूप छावनी परिषद को किसी भी तरह की हानि, दायित्व, मौद्रिक या अन्यथा का सामना करना पड़ता है, तो छावनी परिषद



मौद्रिक रूप में नुकसान या दायित्व की सीमा तक कंपनी के बकाया बिलों या प्रदर्शन, प्रतिभूति जमा से खुद की प्रतिपूर्ति किए जाने की हकदार होगी।

- 3.4.60 ठेकेदार/एजेंसी द्वारा, अपने आउटसोर्स कार्मिकों/कर्मचारियों को श्रम विभाग के आदेशों के अनुरूप न्यूनतम वेतन के साथ-साथ ईपीएफ/ईएसआई/जीएसटी/सेस आदि हेतु अनिवार्य भुगतान, जैसा भी लागू हो, किया जाएगा। बराबरी या समान दरों के मामले में एजेंसी के चयन हेतु सीईओ/परिषद का निर्णय अंतिम होगा। सेवा शुल्क एक बार तय हो जाने के बाद अनुबंध की पूरी अवधि या तत्काल-बाद के विस्तार की अवधि के लिए वही रहेंगे तथा परिषद द्वारा तय मजदूरी से भिन्न नहीं होंगे, या अन्यथा बोर्ड अपने निर्णय के अनुसार आउटसोर्स जनशक्ति की दर/मजदूरी को संशोधित कर सकता है और उसी के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा/आउटसोर्स जनशक्ति को संशोधित मजदूरी का भुगतान, संबंधित विभाग की अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा।
- 3.4.61 ठेकेदार/एजेंसी आउटसोर्स कर्मचारियों के उपस्थिति पत्रक के साथ तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करेगा/करेगी।
- 3.4.62 तैनात कार्मिकों को दिए गए वेतन, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि और जीएसटी आदि के संबंध में बिलों में दावे, आवश्यक रूप से, कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-सत्यापित दस्तावेजी प्रमाण के साथ होने चाहिए, सम्बद्ध महीने के बिल से संबंधित (आउटसोर्स किए गए कार्मिकों के ईएसआई, पीएफ आदि हेतु किए गए योगदान को दिखाने वाले भुगतान की अनुसूची की प्रति के साथ)। बिल के अपेक्षित भाग/पूरे बिल को, प्रमाण प्रस्तुत होने तक, छावनी परिषद चकराता के विवेक पर, रोक कर रखा जाएगा।
- 3.4.63 एल1 के आधार पर बोली स्वीकृत की जाएगी। यदि दो या अधिक बोलीदाताओं के बीच दरें बराबर छूटती हैं तो ऑटो रन एल1/ या उस समय जीईएम में उपलब्ध फंक्शनल्टी या परिषद/सीईओ अपने विवेक से बोलीदाता का चयन करेगा या टाई के मामले में बोलीदाता के पिछले अनुभव को वरीयता दी जाएगी, जो परिषद को पहले भी ऐसी सेवाएं दे चुका हो। इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.4.64 परिषद का, बिना किसी दायित्व या ऐसे किसी भी नुकसान के, जो इस प्रक्रिया में बोलीदाता को हो सकता हो, ऐसी किसी भी बोली (सबसे कम बोली सहित) को अस्वीकार किए जाने का अधिकार सुरक्षित है, जो उसके विचार में अनुक्रियाशील नहीं है या किसी भी शर्त/विनिर्देश का उल्लंघन करती है या जो अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाती पाई गई हो।
- 3.4.65 तैनात किए गए कार्मिक उचित वर्दी में स्मार्ट कपड़े पहने हुये व हमेशा पहचान पत्र के साथ रहेंगे। एजेंसी पूर्ण प्रशिक्षित एवं अनुशासित कार्मिक उपलब्ध कराएगी, जिनका आचरण एवं शिष्टाचार अच्छा होना चाहिए। छावनी परिषद चकराता आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई वर्दी, कार्ड आदि उपलब्ध नहीं कराएगी।
- 3.4.66 ठेकेदार को उसके द्वारा नियुक्त कार्मिकों के लिए वर्दी, पहचान पत्र तैयार कराने, मुआवजा, वेतन एवं अन्य लागू पारिश्रमिक से संबंधित सभी खर्च वहन करना होगा तथा साप्ताहिक अवकाश एवं कार्य घंटों सहित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा। ठेकेदार को प्रत्येक आगामी माह की 7 तारीख को या उससे पहले कार्मिकों को वेतन का भुगतान करना होगा, भले ही छावनी परिषद चकराता द्वारा बिल के भुगतान में किसी

भी कारण से देरी हुई हो। देय वेतन सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतन भुगतान अथवा मामले में परिषद द्वारा निर्धारित देय वेतन से कम नहीं होगा।

3.4.67 ठेकेदार को परिषद के समक्ष कर्मचारियों का ईपीएफ नंबर तथा उसके द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों के संबंध में मासिक बिल के साथ, लागू अनुसार प्रत्येक माह पिछले माह के लिए ईपीएफ, ईएसआई आदि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जनशक्ति- एजेंसी विशेष रूप से निम्नलिखित सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, विभिन्न श्रम कानूनों/अधिनियमों और उनके पुनः अधिनियमन/संशोधन/परिवर्तनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:

मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

कारखाना अधिनियम, 1948

ठेका मजदूर (विनियमन) अधिनियम, 1970

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

बाल रोजगार अधिनियम, 1938

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

3.4.68 यदि ठेकेदार किसी भी कार्मिक को बदलना चाहता है, तो ऐसा परिषद के साथ पूर्व परामर्श के बाद किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा तैनात किए जाने वाले कार्मिकों का पूरा विवरण, नाम और पता सहित, उन्हें काम के लिए वास्तव में तैनात किए जाने से पूर्व प्रशंसापत्र के साथ परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

3.4.69 यदि जनशक्ति - एजेंसी द्वारा तैनात कार्मिकों की ओर से अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय की गई चूक के कारण बोर्ड को कोई नुकसान होता है, तो ऐसे नुकसान की भरपाई संविदा एजेंसी द्वारा की जाएगी और इस संबंध में, परिषद को, जुर्माना लगाये जाने के अलावा, अपने नुकसान की भरपाई के लिए बिल आदि से उचित राशि काटने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात कार्मिकों की ओर से किसी भी तरह की कमी/चूक के मामले में, परिषद को बिना कोई कारण बताए संविदा तुरंत समाप्त करने या कोई अन्य कार्रवाई किए जाने का अधिकार होगा।

3.4.70 यदि कर्तव्य निर्वहन के दौरान कोई मृत्यु या दुर्घटना होती है, तो मुआवजे का एकमेव दायित्व ठेकेदार का होगा।

3.4.71 ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि (स्वामी/निदेशक/भागीदार/प्रबंधक) ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर फीडबैक प्राप्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सीईओ छावनी परिषद चकराता से महीने में कम से कम एक बार संपर्क करेंगे, अर्थात् सेवाओं को और अधिक कुशल बनाये जाने के लिए वांछित सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

3.4.72 यदि संविदा कार्मिक छुट्टी पर हैं या अनुपस्थित हैं, तो ठेकेदार ऐसी अनुपस्थिति के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, ठेकेदार, कर्मचारियों की आरक्षित सूची (रिजर्व इनवेंटरी) अनुरक्षित करेगा; इसमें असफल रहने



परप्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500/- रुपये का जुर्माना लगेगा जो ड्यूटी से गायब या अनुपस्थित पाये जाते हैं, यह जुर्माना ऐसी अनुपस्थिति के लिए ठेकेदार को देना होगा।

- 3.4.73 सफल बोलीदाता को वार्षिक संविदा मूल्य की 5% (पांच प्रतिशत) धनराशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में सीईओ, चकराता छावनी परिषद के पक्ष में, चकराता में देय, ई-छावनी मॉड्यूल के माध्यम से जमा करनी होगी जो संविदा अवधि के दौरान परिषद के पास रहेगी और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.4.74 ठेकेदार को अपने द्वारा तैनात किए गए संविदा कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति का अभिलेख (रिकॉर्ड) अनुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करनी होगी। यह उपस्थिति रिकॉर्ड संबंधित कार्मिकों के उपस्थिति रिकॉर्ड की सत्यापित फोटो कॉपी के साथ परिषद को हर महीने प्रस्तुत किया जाना होगा। किसी भी अन्य समय, छावनी परिषद चकराता द्वारा मांगे जाने पर, उपस्थिति रिकॉर्ड सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। परिषद, ठेकेदार/फर्म द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों की उपस्थिति लिए जाने हेतु, आधार, आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित कर सकती है।
- 3.4.76 इस संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में, पी.डी.डी.ई., सी.सी. लखनऊ विवाद में शामिल मुद्दे पर निर्णय लिए जाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में किसी अधिकारी को नामित करेगा तथा इसपर मध्यस्थता-अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। सेवाएं प्रदान किए जाने तथा अनुबंध के किसी खंड की व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, चकराता/विकास नगर/देहरादून/उत्तराखंड के न्यायालयों का सभी विवादों को निपटाने तथा निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र होगा।
- 3.4.77 जब भी परिषद को अस्थायी या आपातकालीन आधार पर अतिरिक्त संविदा कार्मिकों की आवश्यकता होगी, तो ठेकेदार ऐसे कार्मिकों को आनुपातिक दरों के अनुसार प्रतिनियुक्त करेगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।
- 3.4.78 अनुदेशों/अनुबंध का उल्लंघन किए जाने या तथ्यों को छिपाये जाने पर बिना किसी संदर्भ के अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
- 3.4.79 यदि परिषद को संदेह हो या पता चले कि कोई कार्य किसी उप-ठेकेदार को टुकड़ों-टुकड़ों में या नियमित रूप में सौंपा गया है, तो बिना कोई कारण बताए संविदा समाप्त किए जाने का परिषद का अधिकार सुरक्षित है।
- 3.4.80 दिन-प्रतिदिन के कार्यों में लगे कार्मिकों का उपयोग ऐसे यदा-कदा के कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए ठेकेदार को अतिरिक्त कार्मिकों को लगाना पड़ता।
- 3.4.81 किन्हीं भी ऐसे प्रावधान/नियम का उल्लंघन/अनुपालन न किए जाने के लिए वैधानिक निकायों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई हेतु ठेकेदार को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा।
- 3.4.82 ठेकेदार को हर समय, विभिन्न अधिनियमों/नियमों/कानूनों के तहत ठेका मजदूरों/कार्मिकों पर लागू सभी वैधानिक रिकॉर्ड और दस्तावेज को निर्धारित उचित प्रारूप में रखन होगा तथा संबंधित अधिनियमों/नियमों/कानूनों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर संबंधित अधिकारियों को उचित प्रारूप में सभी निर्धारित रिटर्न दाखिल किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

24/10/20

23/10/20



- 3.4.83 परिषद द्वारा मांगे जाने पर, ठेकेदार द्वारा ऐसे सभी अभिलेख/दस्तावेज/विवरण, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने होंगे, जिन्हें परिषद लागू अधिनियमों/नियमों/कानूनों के प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे।
- 3.4.84 ठेकेदार के पास ठेका श्रम अधिनियम के अनुसार ठेका श्रमिक/कार्मिकों को नियुक्त किए जाने हेतु श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त लाइसेंस होना चाहिए।
- 3.4.85 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा किए जाने हेतु तैनात कर्मकारों को मजदूरी का भुगतान उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी जो भी संविदा अवधि के दौरान लागू हो या मामले में हो सकता है कि परिषद द्वारा कुछ या संपूर्ण पद के लिए निर्धारित हो, से कम न हो।
- 3.4.86 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मकारों को प्रत्येक आगामी माह की 7 तारीख को या उससे पहले मजदूरी का भुगतान हो जाए। मजदूरी का भुगतान परिषद के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित स्थान और समय पर किया जाएगा।
- 3.4.87 वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मकारों को छोड़कर अन्य सभी कर्मकारों को बिना किसी कटौती के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- 3.4.88 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कर्मकारों को, मजदूरी के साथ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हेतु लागू, प्रासंगिक अधिनियम/नियमों के अनुसार अवकाश/छुट्टियां प्रदान की जाएं।
- 3.4.89 यदि ठेकेदार ईएसआई/पीएफ देय राशि के भुगतान किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो छावनी परिषद चकराता का बिल रोकने का अधिकार सुरक्षित है।
- 3.4.90 ठेकेदार को छावनी परिषद चकराता में कार्यरत अपने सभी कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराना होगा तथा मतदाता पहचान पत्र व निवास और योग्यता के अन्य वैध प्रमाण के साथ रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। ठेकेदार को अपने मतदाता पहचान पत्र, पैन, आवासीय पता, शैक्षिक योग्यता आदि की सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
- 3.4.91 यदि ठेकेदार का कोई कार्मिक चोरी या किसी अवैध/अनियमित गतिविधि, कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो ठेकेदार इस कार्यालय के परामर्श से अपने दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कानून और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को देगा। ऐसे कार्मिक, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय में आगे नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।
- 3.4.92 जब कभी भी नियम और शर्तों या अनुबंध में किसी खंड का दोहराव हुआ हो, तो किसी भी विवाद/किसी वैधानिक नियमों का पालन किए जाते समय छावनी परिषद चकराता हेतु लाभकारी खंड ही लागू माना जाएगा।
- 3.4.93 परिषद के साथ समन्वय किए जाने तथा छावनी परिषद चकराता की संतुष्टि हेतु तैनात कार्मिकों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी के लिए ठेकेदार, अपनी ओर से कम से कम एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। कार्य प्रारंभ होने से पूर्व पर्यवेक्षक का विवरण छावनी परिषद चकराता को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा तथा किसी भी परिवर्तन की सूचना भी विधिवत दी जाएगी।



- 3.4.94 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात कार्मिकों को वेतन भुगतान में देरी के कारण किसी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश न रहे।
- 3.4.95 कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य के संतोषजनक समापन के पश्चात मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 3.4.96 संविदा के तहत किसी दायित्व की पूर्ति न किए जाने की किसी शिकायत के मामले में, सीईओ, छावनी परिषद चकराता का, ठेकेदार द्वारा देय भुगतान को, मासिक बिल/बिलों से काट लिए जाने का अधिकार सुरक्षित है।
- 3.4.97 प्रत्येक कर्मचारी को वेतन के रूप में किए गए भुगतान के लिए चालान/रसीद का प्रमाण, प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक शुल्क बिल के साथ, इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि इस कार्यालय को, किसी कार्मिक को वेतन का भुगतान न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इन कार्मिकों को देय राशि ठेकेदार के बिल से वसूल करके ऐसे कार्मिकों का भुगतान कर दिया जाएगा। ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। ठेकेदार कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान को प्रतिमाह नामित प्राधिकारी के पास निर्दिष्ट खाते में जमा करेगा। प्रत्येक चालू बिल के साथ ठेकेदार को श्रमिकों के खाते में पिछले माह किए गए भविष्य निधि एवं ईएसआई के भुगतान का चालान/रसीद तथा उनका ईएसआईसी बीमा क्रमांक/ईपीएफ अंशदाता क्रमांक प्रस्तुत करना होगा।
- 3.4.98 छावनी परिषद चकराता ठेकेदार को संविदा के अनुसार मासिक आधार पर केवल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा तथा कोई अन्य भुगतान जैसे पीएफ/ईएसआई/सेवाकर आदि ठेकेदार द्वारा संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों/खातों में भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही किए जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस, परफॉरमेंस बोनस जैसे अन्य भुगतान नहीं किए जाएंगे।
- 3.4.99 निविदा सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 और उसके संशोधन के अनुसार प्रदान की जाएगी।
- 3.4.100 सभी निविदाएं भारत सरकार के एमएसएमई वरीयता अनुदेशों और समय-समय पर उसमें संशोधन के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

\*\*\*\*\*

नोट: ये नियम और शर्तें, संविदा / अनुबंध का हिस्सा हैं, जैसा कि छावनी परिषद चकराता और एजेंसी के बीच समझौते में दर्शाया गया है, तथा किसी भी गैर-अनुपालन को संविदा/अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

23/12  
(आर.एन. मंडल)  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद चकराता

	<p align="center"><b>OFFICE OF THE CANTONMENT BOARD CHAKRATA CANTT.</b> कार्यालय छावनी परिषद, चकराता <b>Phone/फोन: 01360- 272220, Fax/फैक्स 01360- 272502</b> <b>Email/ई.मेल: <a href="mailto:ceochak-stats@nic.in">ceochak-stats@nic.in</a></b></p>	
---	--	--

File No. 6/6/Contract/Teacher/2024

Dated 27 July, 2024

**SUB:- NOTICE INVITING TENDER FOR SUPPLY OF TEACHERS ON OUTSOURCED BASIS TO CANTONMENT BOARD CHAKRATA SCHOOLS, BY DEPLOYING REQUIRED NUMBER OF OUTSOURCED TEACHERS ON FIXED HONORARIUM**

Online tender invited from eligible bidders for supply of teachers on outsourced basis for various Schools in Cantt Board Chakrata through the Government e-Market portal i.e. <https://gem.gov.in>. The detail of tender is as under:-

**1. PARTICULARS OF TENDER**

Particulars of the work	<b>SUPPLY OF TEACHERS ON OUTSOURCED BASIS TO CANTONMENT BOARD CHAKRATA SCHOOLS, BY DEPLOYING REQUIRED NUMBER OF OUTSOURCED TEACHERS ON FIXED HONORARIUM</b>
Estimated Budget of Contract	<b>Rs. 48,00,000/-</b>
Period of contract	1 year
Tender fee	Rs. 5900.00 Through e-chhawani module. Exemption allowed as per Govt. of India rules/guidelines
Amount earnest money	Rs. 1,00,000/- Through e-chhawani module. Exemption allowed as per Govt. of India rules/guidelines issued time to time.
Last date and time of submission of Bid	19-08-2024 (Time as display on GEM Portal)
Date and time of tender opening	19-08-2024 (Time as display on GEM Portal)

The CEO/Board reserves the right to increase/decrease the estimated cost of works and to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason.

Further details may be obtained from <https://gem.gov.in> . For any clarification contact to the Office of Cantonment Board, Chakrata on any working day during office hours. The bidder is advised to examine carefully all instructions, conditions, forms, terms and specifications, bill of quantity etc. in the bid document. Tenders will be accepted via online mode only. On participating this tender bidder is suppose to read and understand the terms and condition of tender. No deviation will be accepted by the competent authority by the bidder made in online tender in case may be.

Note:- All update/Corrigendum, submission will be available on Government e-Market Portal i.e. <https://gem.gov.in> For tender documents you can visit Cantt Board website also:- <https://chakrata.cantt.gov.in>

  
(R.N. Mandal)

Chief Executive Officer  
Cantonment Board, Chakrata.

**Note: - In case of discrepancies, if any, found between the English text version and Hindi translation, the English version shall prevail.**



## **2. ELIGIBILITY CRITERIA**

Cantonment Board Chakrata invites offers/quotations from Contractors/firms/ agencies/ organizations for **SUPPLY OF TEACHERS ON OUTSOURCED BASIS TO CANTONMENT BOARD CHAKRATA SCHOOLS, BY DEPLOYING REQUIRED NUMBER OF OUTSOURCED TEACHERS ON FIXED HONORARIUM**. Firms/ agencies/ organizations fulfilling the following eligibility criteria may apply tender/upload documents in GEM. The EMD and tender cost will be deposited into the Cantonment Board Chakrata through E-Chhawani online platform. The link for echhawani is <https://echhawani.gov.in> , bidder also download echhawani app from the play store. The bidding firms must submit documentary evidence in respect of the following eligibility criteria along with their bids. Bids/Tenders without proper documents shall be rejected straightway. As per CBR No. 05, dated 06-10-2023 minimum service charges are fixed to at par with GEM i.e. 3.85% currently.

### **2.a Eligibility Criteria:**

Following conditions must be fulfilled by the bidder. The required details and supporting documents in this regard should be submitted along with the form for Technical Bid. All the documents should be numbered and enclosed as annexure.

1. The Contractor/Agency should have work experience of providing manpower (in last three year i.e 2020-21, 2021-22 and 2022-23) from Central Govt./State Govt./Cantonment Board/Municipal Corporation or any Govt Deptt/Agency. Minimum Rs. 20,00,000/- (Rs. Twenty lakh). Exemption from experience allowed as per Govt. of India rules/guidelines issued time to time on uploading the requisite certificate.
2. The Contractor/Agency average annual turnover should be not less than 40 lakh in last three year (any one or combined in three year)( i.e. 2020-21, 2021-22 and 2022-23) which should be reflected in Audited Balance Sheet or certificate in this regard from Chartered Accountant. Exemption from turnover allowed as per Govt. of India rules/guidelines issued time to time on uploading the requisite certificate.
3. The contractor/agency should also furnish copies of all the registration certificates under the various rules & regulations as applicable in its case such as **EPF, ESI & GST Registration and PAN CARD**.
4. Contractor/agency should enclose the copy of valid labour licence.
5. **Outsourced personal/employees provided by the contractor/agency** must be above 18 years of age as per the rule of Labour Dept.
6. The salary shall be payable to the outsourced employees as per **rule of Labour Deptt.** or as fixed by the board or minimum wages published by Central Govt/State Govt or its own discretion of Board .
7. The **contractor/agency** should be capable of providing at least 3 months' salary to the **Outsourced personnel/employee** in advance. A declaration in this regard is submitted by the contractor/agency who's tender accepted by the Board.
8. Contractor/agency shall submit affidavit stating that the Contractor/agency is not / has not been black listed by any Ministry/Department of Government of India/ any State Govt/ Private Sector Companies/PSUs/Banks etc.



### 3. TERMS AND CONDITION

#### 3.1. SCOPE OF WORK

**SUPPLY OF TEACHERS ON OUTSOURCED BASIS TO CANTONMENT BOARD CHAKRATA SCHOOLS, BY DEPLOYING REQUIRED NUMBER OF OUTSOURCED TEACHERS ON FIXED HONORARIUM**

#### 3.2. NAME OF CONTRACT

**SUPPLY OF TEACHERS ON OUTSOURCED BASIS TO CANTONMENT BOARD CHAKRATA SCHOOLS, BY DEPLOYING REQUIRED NUMBER OF OUTSOURCED TEACHERS ON FIXED HONORARIUM**

#### 3.3. PERIOD OF CONTRACT

The contract shall be for a period of one year from the date of commencement and further extended upto 4 year on year to year basis or period for which Board/CEO decide the extension of contract. The period of contract, may be terminated by the board, provided that the requirement of the Cantonment Board for persons persists at that time or may be curtailed / terminated before the contract period owing to deficiency in service or substandard quality of manpower deployed by the selected agency or cessation of the requirement of the work. The Cantonment Board Chakrata or Chief Executive Officer reserves the right to terminate this initial contract at any time after giving one month's notice to the selected agency. TENDER WILL BE AWARDED AS PER PUBLIC PROCUREMENT (PREFERENCE TO MAKE IN INDIA) ORDER 2017 AND ITS AMENDMENT. Cantonment Board/Chief Executive Officer reserves the right to increase/decrease the number of **Outsourced personnel/employee/Outsourced Teachers** depending upon its functional requirement.

#### 3.4. GENERAL TERMS AND CONDITION

3.4.1. The job of the contractor/agency shall be of SUPPLY OF TEACHERS ON OUTSOURCED BASIS TO CANTONMENT BOARD CHAKRATA SCHOOLS, BY DEPLOYING REQUIRED NUMBER OF OUTSOURCED TEACHERS ON FIXED HONORARIUM the contractor/agency have no right over the building & other infrastructure, furniture & fixtures which shall remain the property of Cantonment Board, Chakrata that shall be responsible for maintaining the same.

3.4.2 All Central Govt/State Govt etc charges/taxes liable on contract will have to be paid by contractor and same will reimbursed by Cantt Board to Contractor on production of the receipt of the same. Any new charges/taxes lived by Govt same will be paid by Board as per rule.





3.4.3 Monthly payment will only be made on the basis of attendance and satisfactory work done by contractor, deduction of absentees will be done on the basis of current minimum wages/fixed remuneration.

3.4.4 Apart from submitting the tender documents online, the interested companies/bidder are also required to submit Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 1,00,000/- and tender cost of Rs. 5900/- through EChhawani into Cantonment Board, Chakrata and receipt of the same upload in online bid. Exemption will be allowed for the concerned firm/contractor/bidder as per Govt of India order for EMD and Tender cost on attachment of the copy of certificate in online Bid.

3.4.5 The successful bidder shall furnish the security deposit (5% or higher as per Govt of India order time to time) of tender estimated amount/value of contract or the rate decided by Govt of India time to time through e-chhawani module in Cantonment Board, Chakrata. The Security deposited will be refunded after the termination of contract.

3.4.6 The tenders have been published in <https://gem.gov.in> . The interested agencies/bidder are advised to bid online at <https://gem.gov.in> as per procedure in GEM(Government e Market).

3.4.7 The Technical bid/documents shall be opened first on the scheduled date and time at Office of the Cantonment Board, Chakrata(in GEM portal) in presence of the representatives of the company, if any, who wish to be present on the spot at that time. The Technical Bids shall be evaluated by a Technical Bid Evaluation Committee. Financial bids of technically qualified eligible bidders meeting criteria only shall be opened on the scheduled date and time as at (in GEM Portal)office of the Cantonment Board Chakrata in presence of short-listed contractors or their authorized representatives if any.

3.4.8 The bidder shall quote the technical & financial bid in GEM Portal only.

3.4.9 Conditional bids shall not be considered and will be summarily rejected.

3.4.10 The Chief Executive Officer shall have absolute rights and powers to forfeit the said security deposit in case of breach of any clause of this contract without any prior notice to the contractor and no claim whatsoever on this account shall be entertained.

3.4.11. The penalty @ 1% or more of the monthly value of the contract shall be imposed for non commencement of the services within 7 days after the issue of requisition for the **Outsourced personnel**. The Chief Executive Officer shall have the power to condone the delay, reduce or remit the penalty so imposed to any extent, on the written application of the contract, in case the authority competent to do so finds that the grounds given by the contractor are reasonable and satisfactory.

3.4.12. The decision of the Cantonment Board, Chakrata with regard to the determining of quality of worker provided by the contractor, shall be final and acceptable to the contractor. If any deficiency is found with regard the services by the **Outsourced personnel** so deployed



by the contractor, the contractor shall, therefore rectify the defect so pointed out without any extra payment. The Board shall also reserve the rights to get the services rejected or done/replaced at his own level at the risk and cost of contractor, after giving him a notice in writing and expenditure incurred on this account shall be recovered from the bills of the contractor of any other outsourcing dues or by forfeiting of any or all parts of the security/bank guarantee, as the Board may think proper.

3.4.13. The contractor shall be informed well in advance the number of **Outsourced personnel** to be deployed to the Cantonment Board Chakrata. The contractor shall deploy required personnel to provide the said service and immediately communicate the name, parentage, residential address, age proof, certified true copies of their academic and professional/technical qualification on account of their jobs, Aadhar Card, Mobile No. etc, of the persons as and when deployed or changed from time to time.

3.4.14. For the purpose of proper identification of the employees of the contractor, the contractor shall himself issue them the Identity Cards/Identification document and they shall be duty bound to display the Identity Cards at the time of duty.

3.4.15. The Chief Executive Officer or any other person so authorized by him/her shall be at liberty to carry out any surprise check on the working of the persons so deployed by the contractor in order to ensure that the required numbers of persons are deployed and that they are doing their duties properly.

3.4.16. On taking over the responsibility of providing the said service, the contractor shall formulate the mechanism and working guide-lines for the **Outsourced personnel** in consultation with the Chief Executive Officer. The contractor will keep on reviewing his arrangements from time to time and take additional measures, if any required to be taken to further streamline the said arrangement. The contractor as well as the **Outsourced personnel** deployed on duty shall however be bound to carry out the directions/instructions given to them to do any such job(s) assigned by the Chief Executive Officer.

3.4.17. The persons deployed by the contractor/agency for the work shall be employees of the contractor/agency for all intents and purposes. In other words the contractor/agency shall be the employer of the outsourced personnel/employees so deployed by the concerned contractor/agency and the Cantonment Board, Chakrata will not be treated as employer to the employees/persons in any respect.

3.4.18. The contractor/agency will ensure that employees are medically fit.

3.4.19. The persons so deployed shall be under the overall control and supervision of the contractor and the contractor shall be liable for payment of their wages etc. and all other dues which the contractor is liable to pay under the various labour regulation and other statutory provisions. The Cantonment Board, Chakrata shall be absolved of any such liability at its own level.



3.4.20. The contractor/agency shall ensure that all the employees get wages and other benefits admissible under various Labour Laws, as applicable.

3.4.21. The contractor/agency shall be responsible for fulfilling all his obligations towards the persons deployed under law, namely under the Minimum Wages Act, P.F. Act, ESI Act, Bonus Act, Maternity Benefit Act, Shops and Establishment Act etc, if applicable. The contractor shall be responsible for contributions to the ESI, EOF, EDLI, if applicable at his own level and maintained of such records as per rules. The contractor shall arrange the disbursement of wages to his **Outsourced personnel** so deployed for duty by 07th of every month. At the time of submission of bill for payment, the contractor should submit the proof for the previous payment made towards statutory liabilities like **EPF, ESI, GST (as applicable)** or other Central/State Govt. taxes enforced etc. in respect of all the engaged personnel along with the attendance report of the **Outsourced personnel** deployed duly certified by the authorized official of the Cantonment Board and the same will be paid by cantonment Board. The contractor will also furnish a certificate regarding payment of honorarium/Dues to the **Outsourced personnel** deployed. The Board shall make the payment within one week of the receipt of the bill in proper form. The Cantonment Board, Chakrata shall in no case be involved or liable for any dispute between the **Outsourced personnel** deployed and the contractor regarding disbursement of the salaries or otherwise. The contractor shall be solely responsible for any lapse or delay for the submission of the return to the concerned authority of labour department EPF, ESI etc. about the **outsourced personal** in this Cantonment Board on contract basis if so required.

3.4.22. In case any of the persons so deployed by the contractor does not come upto the mark or performs his/her duties properly or indulges in any unlawful acts or disorderly conduct, the contractor shall take suitable action against such employee on the report of Chief Executive Officer or any other Officer/Official so authorized by the CEO for the purpose in this respect.

3.4.23. In case of any complaint, defect pointed out by the CEO/Board with regard the persons deployed by the contractor, the contractor shall immediately replace the particular person so deployed without further arguments.

3.4.24. The contractor/agency shall ensure that the **Outsourced personnel** so deployed adhere to the time schedule and leave schedule as fixed by the Board from time to time. In case of any long absence i.e. more than 7 days, the contractor shall ensure for stop gap arrangement.

3.4.25. The contractor/agency shall keep the Board indemnified against any loss caused to the Board's property by way of theft, mishandling or otherwise and the claims whatsoever in respect of the employees deployed by the contractor. The contractor/agency shall be responsible for paying the recovery of amount of any loss caused to the movable/immovable property of the Board. In case any employee of the contractor/agency so deployed enters into dispute of any nature whatsoever, it will be the sole responsibility of the contractor concerned to contest the same. In case the Board is also made a party and is supposed to contest the case, the cost if any of the actual expenses incurred towards counsel fee and other expenses shall be paid to the Board by the contractor in advance on demand. Further the contractor



shall ensure that no financial or any other legal liability comes on the Board in this respect of any nature whatsoever for the act done by the persons of the contractor and shall keep the Board indemnified in this respect.

3.4.26. The Board has further right to adjust or readjust or deduct any of the amounts from the payment to be made to the contractor/agency under this contract or out of the security deposits of the contractor/agency.

3.4.27. Both of parties will be liable to adjust the amount (even after the completion of contract period).

3.4.28. If the contractor/agency has not paid salary to any of the **Outsourced personnel** so deployed, the Board will have the right to adjust or readjust or deduct the salary of the said employee, as aforesaid from the payment to be made to the contract under this contract or out of the security deposit of the contractor.

3.4.29. The contractor/agency shall be solely responsible for any damage/compensation due to injury/death of any staff deployed while on duty.

3.4.30. In case of any deficiency in services by the staff so deployed on contract basis or in the case of disobedience by the staff so deployed on duty, the Chief Executive Officer or any officer/official so authorized by the CEO shall be at liberty for the imposition of penalty, as may be deemed fit upto Rs. 500/- on such occasion after giving him an opportunity of being heard in person and the decision of the Chief Executive Officer shall be final and binding to the contractor.

3.4.31. The contractor/agency shall be responsible for payment of wages to each worker employed by him as contract labour and such wages shall be paid 7<sup>th</sup> day of every month and to ensure the disbursement of wages deposited in bank account of his daily workers /outsourced staff directly. No cash payments at all.

3.4.32. The contractor/agency would be responsible for wages that would be directly go to bank account of the daily workers/outsourced staff. The Accountant of the Cantonment Board Charkata is authorized to check and fully satisfied that salary, EPF, ESIC if any, GST etc deposited in authorized account before release the payment of bills of contractor.

3.4.33. The contract may be terminated in any of the following contingencies:

(a) On the expiry of the contract period.

(b) A notice of one month at any time during the continuation of services, in case the services rendered by the contractor/agency are not found satisfactory and in conformity with the general norm and the standard prescribed for the services.

or

(c) For committing breach of any of the terms and conditions of the contract by the contractor.

or

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



(d) On assigning the contract or any part thereof any benefit or interest therein or there under by the contractor to any third person for sub-letting the whole or a part of the contract to any third person.

(e) On contractor/agency being declared insolvent by competent court of law. During the notice period for termination of the contract in the situation contemplated above, the contractor/agency shall keep on discharging his duties as before till the expiry of notice periods. It shall be the duty of the contractor to remove all the persons deployed by him on termination of the contract on any ground whatsoever and ensure that no person shall create any disruption/hindrance/problem of any nature to the board.

3.4.34. Contractor/agency shall not be allowed to transfer, assign, pledge or sub-contract its rights and liabilities under this contract to another Company without the prior written consent and permission of the Cantonment Board, Chakrata.

3.4.35. Financial bids of only those tenderers who are declared qualified technically shall be evaluated.

3.4.36. The Cantonment Board, Chakrata reserves right to terminate the contract during initial period also after giving one months' notice to the contracting Company.

3.4.37. Contractor/agency shall furnish before the commencement of work, the following documents in respect of the persons who are proposed to be deployed in the Cantonment Board- Aadhar Card, Educational Qualification, permanent address proof etc.

3.4.38. List of persons full details i.e. date of birth, marital status, address, educational and professional qualification, experience etc.

3.4.39. In case, the person employed by the successful contractor/agency commits any act of omission or commission that amounts to misconduct / indiscipline/ incompetence/ malfeasance/ security risk, the Service Provider will be liable to take immediate appropriate action against such persons, including registering a police case for the malfeasance/being security risk and their removal from site of work, within 1 day of being brought to their notice.

3.4.40. Contractor/agency shall provide large identity cards to the personnel deployed in the Cantonment Board recent photograph of the personnel and personal information as to name, date of birth, designation and identification mark etc.

3.4.41. Contractor/agency shall ensure proper conduct of its personnel in office premises, and enforce prohibition of consumption of alcoholic drinks, paan, smoking, loitering etc. The service provider will also ensure that the personnel adhere to the dress code commensurate with a government office.

3.4.42. The agency shall depute a coordinator, who would be responsible for interaction with the CANTONMENT BOARD CHAKRATA so that optimal services can be availed without any disruption.

3.4.43. For all intents and purposes, the contractor shall be the "Employer" within the meaning of different Labour Legislations in respect of personnel so employed and deployed in the Cantonment Board, Chakrata. **The persons deployed by the contractor in the Cantonment Board shall not have claims of any Employer and Employee relationship nor have any principal and agent relationship with or against Cantonment Board, Chakrata.**





3.4.44. The contractor/agency shall be solely responsible for the redressing grievances / resolution of disputes relating to persons deployed. The Cantonment Board, Chakrata shall, in no way, be responsible for settlement of such issues whatsoever.

3.4.45. This Cantonment Board Chakrata shall not be responsible for any damages, losses, claims, financial or other injury to any person deployed by service providing Company in the course of their performing the functions/ duties, or for payment towards any compensation.

3.4.46. The persons deployed by the contractor shall not claim nor shall be entitled to pay, perks and other facilities admissible to casual, ad hoc, regular/ confirmed employees of the Cantonment Board during the currency or after expiry of the contract.

3.4.47. In case of termination of this contract on its expiry or otherwise, the persons deployed by the Contractor shall not be entitled to and will have no claim, for any absorption nor for any relaxation for absorption in the regular/ other capacity.

3.4.48. In the event of exigencies arising due to the death, infirmity, insolvency of the contractor or for any other reason or circumstances, liabilities thereof of the contract shall be drawn by the following on such terms and conditions, as the Board may think fit.

- (i) Legal heirs in case of sole proprietor
- (ii) The next partners in case of company of firm otherwise the Chief Executive Officer shall reserve the right to settle the matter according to the circumstances of the case as he/she may think proper.

3.4.49. Contractor/agency shall not be allowed to be represented by a lawyer during any investigation, enquiry with regard to the dispute during the functioning the contract work by outsourced personnel/employees.

3.4.50. All the disputes in regard to this contract shall be subject to jurisdiction of Chakrata/Vikas Nagar/Dehradun/Uttarakhand Court only.

3.4.51. In the event of any dispute or differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement whatsoever, the same shall be referred to the sole Arbitrator (PDDE, Central Command, Lucknow or any Other Officer as decided by the CEO/Board), whose decision shall be final and binding on the parties thereof. Arbitration will be governed as per Arbitration Act, and its amendment time to time.

3.4.52. The right of the cancellation/rejection of tendering process (fully or partially) will be decided by Chief Executive Officer/Cantt Board, Chakrata without prejudice.

3.4.53. The qualification of technical persons in case may be i.e. teachers, Clerk, other technical staff, MTS staff etc. will be decided by Chief Executive Officer, Cantonment Board, Chakrata/Board or the Educational Qualification as per permanent post against the outsourced staff hired. The agency will publish advertisement or as per decision of the Board/CEO for engagement of staff at his own cost whose reimbursement will be provided on production of the bills etc and will provide the shortlist of candidate to this office for engagement and the CEO will select the candidate for engagement of technical/Non technical/ MTS job requirement as per their qualifications.



3.4.54 Contractor/agency should be registered/incorporated as a company under Indian Companies Act in case may be.

3.4.55 Contractor/agency shall be responsible for compliance of all statutory provisions relating to Minimum wages, Provident Fund, and Employees State Insurance etc. in respect of the persons deployed by it in Cantonment Board, Chakrata

3.4.56 Contractor/agency shall also be liable for depositing all taxes, levies, cess etc. on account of service rendered by it to Cantonment Board, Chakrata to concerned tax collection authorities from time to time as per extant rules and regulations on the matter.

3.4.57 Contractor/agency shall maintain all statutory registers under the applicable laws. The Company shall produce the same, on demand, to the concerned authority of Cantonment Board or any other authority under law.

3.4.58 The Tax Deduction at Source (TDS) shall be deducted as per the provisions of Income Tax law, as amended from time to time and a certificate to this effect shall be provided to the Company by Cantonment Board.

3.4.59 In case, the tendering Company fails to comply with any statutory/ taxation liability under appropriate law and as a result thereof the Cantonment Board is put to any loss, obligation, monetary or otherwise, the Cantonment Board will be entitled to get itself reimbursed out of the outstanding bills or the Performance Security Deposit of the Company, to the extent of the loss or obligation in monetary terms.

3.4.60 The contractor/Agency shall be paid to its outsourced personnel/employees as minimum wage as per Labour Deptt Orders plus obligatory payments towards EPF/ESI/GST/Cess etc., as applicable. In the case of tie or equal rates the decision of the CEO/Board for selecting the agency is final. **These service charges once fixed will remain fixed for the entire duration of the contract or for period of subsequent extension(s) and will not vary with the wage as fixed by the Board , or otherwise** THE BOARD AS PER ITS DECISION MAY REVISED THE RATE/WAGES FOR OUTSOURCED MANPOWER AND SAME WILL BE PAID TO CONTRACTOR ACCORDINGLY. The revised wages will be paid to outsourced manpower as per notification of the concerned department.

3.4.61 The contractor/agency shall raise the bill, in triplicate, along with attendance sheet of the outsourced employees.

3.4.62 The claims in bills regarding wages paid to the personnel deployed, Employees State Insurance, Provident Fund, and GST etc. should be necessarily accompanied with documentary proof, duly self-attested by the authorised representative of the company, (including copy of schedule of payment showing contribution towards ESI, PF etc. in respect of the outsourced personnel) pertaining to the concerned month's bill. A requisite portion of the bill/whole of the bill shall be held up till the proof is furnished, at the discretion of the Cantonment Board Chakrata.

3.4.63 Bidding awarded on the basis of L1. In case of rates are tie between two or more bidder the Auto Run L1/ or the functionality available in GEM on that time or Board/ CEO will be select the bidder in its own discretion or past experience of bidder who have already given same services to the Board given preference in tie case. The decision of Board in this regard if final.



3.4.64 The Board reserves the right to reject any bid (including the lowest one) which in its opinion is not responsive or violating any of the conditions/specifications or which is found to be adopting unethical business practices, without bearing any liability or any loss whatsoever it may cause to the bidder in the process.

3.4.65 The personnel deployed shall be smartly dressed in proper uniform and always with Identity Card. The agency shall provide fully trained and disciplined personnel who should be well behaved and well mannered. Cantonment Board Chakrata not provide any uniform, card etc to outsourced employees.

3.4.66 The contractor shall bear all expenses regarding uniforms, preparation of their Identity card, compensations, wages and other applicable remuneration relating to personnel engaged by him and abide by the provisions of various labour legislations including weekly off and working hours. The Contractor shall pay the wages to the personnel on or before the 7th day of every succeeding month, irrespective of delay in payment of Bill by the Cantonment Board Chakrata for whatever reason. Wages payable shall not be less than the minimum wages payment as declared by the Govt time to time or in case fixed by the Board.

3.4.67 The Contractor shall submit workers EPF number and proof of submission of EPF, ESI etc as applicable every month for the previous month along with the monthly bill with respect to all employees deployed by him at Board. The manpower agency shall specifically ensure compliance of various Labour Laws/Acts including but not limited to with the following and their re-enactments/amendments/modifications:

The payment of wages Act 1936

The Employees Provident Fund Act, 1952

The Factory Act, 1948

The Contract Labour (Regulation) Act, 1970

The Payment of Bonus Act, 1965

The Payment of Gratuity Act, 1972

The Employees State Insurance Act, 1948

The Employment of Children Act, 1938

The Motor Vehicle Act, 1988

The Minimum Wages Act, 1948

3.4.68 If the Contractor wishes to replace any of the personnel, the same shall be done after prior consultation with the Board. The full particulars of the personnel to be deployed by the contractor including the names and address shall be furnished to the Board along with testimonials before they are actually deployed for the job.

3.4.69 In case of any loss that might be caused to the Board due to lapse on the part of the personnel deployed by the manpower agency discharging their responsibilities, the such loss



shall be compensated by the contracting Agency and in this connection, the Board shall have the right to deduct appropriate amount from the bill etc. to make good of such loss to the Board besides imposition of penalty. In case of any deficiencies/lapses on the part of the personnel deployed by the contractor, the Board shall be within its right to terminate the contract forthwith or take any other action without assigning any reason whatsoever.

3.4.70 If case of a death or mishap occurred during discharging the duty, the compensation liability will solely rest with the Contractor.

3.4.71 That Contractor's authorized representative (Owner/Director/Partner/Manager) shall personally contact CEO Cantonment Board Chakrata at least once a month to get a feedback on the services rendered by the contractor viza-viz corrective action required to make the services more efficient.

3.4.72 In the event of contract personnel being on leave/absent, the contractor shall ensure suitable alternative arrangement to make up for such absence. To meet such eventualities, the contractor shall maintain reserve inventory of employees; Failure on this account shall attract penalty of Rs.500/- per day per person who is found missing / absent from duty payable by the Contractor for such absence.

3.4.73 The successful bidder would have to deposit an amount of 5% (five percent) of Annual contract of value towards performance security deposit through e-chhawani module in favour of the CEO, Chakrata Cantonment Board payable at Chakrata which would remain with Board during the contract period and no interest shall be payable on the performance Security Deposit amount.

3.4.74 The contractor shall arrange to maintain the daily attendance record of the contract personnel deployed by him. This attendance record is to be submitted every month to the Board with an attested photo- copy of the attendance record of the personnel to which it pertains. The attendance record shall be produced for verification on demand by the Cantonment Board Chakrata at any other point of time. The Board may be install Aadhar based Biometric Attendance machine for taking attendance of staff deployed by contractor/firm.

3.4.76 In case of any dispute arising out of this agreement then PDDE, CC Lucknow shall nominate any officer as a sole arbitrator to adjudicate upon the issue involved in the dispute and the provisions of the Arbitration Act shall be applicable. In case of any dispute with regard to providing services and interpretation of any clause of the Agreement, Chakrata/Vikas Nagar/Dehradun/Uttarakhand Court will have the jurisdiction to settle and decide all the disputes.

3.4.77 As and when the Board requires additional contract personnel on temporary or emergency basis, the contractor will depute such personnel in accordance with pro-rata rates. For the same, a notice of seven days will be given by the Board.

3.4.78 Any violation of instructions/agreement or suppression of facts will attract cancellation of agreement without any reference.



3.4.79 In case the Board suspects or finds any work is entrusted to any sub-contractor on piecemeal basis or on regular terms, the Board reserves the right to terminate the contract without assigning any reasons.

3.4.80 Personnel engaged on day-to-day works should not be utilized for carrying out the occasional work for which contractor has to engage extra personnel.

3.4.81 The contractor will be held wholly responsible for any action taken by statutory bodies for violation/non-compilation of any such provision/rule.

3.4.82 The contractor shall, at all times, maintain all the statutory records and documents, in proper format, as prescribed under the various Acts / Rules / Laws applicable to contract labours/personnel and shall ensure filing of all prescribed return in proper format to the concerned authorities well within the time limit specified under the respective Acts / Rules / Laws.

3.4.83 The contractor shall, on demand by Board, produce all such records / documents / returns for inspection as Board deems fit for ensuring proper compliance towards the provisions of applicable Acts / Rules / Laws is being done by the contractor.

3.4.84 The contractor should have Licence from the Labour Commissioner to engage the Contract labour/personnel as per Contract Labour Act.

3.4.85 The contractor shall ensure that the payment of wages to his workmen deployed for carrying out his contractual obligations shall not be less than the minimum wages prescribed by the Govt of Uttarakhand or Central Govt notified minimum wages, from time to time, as applicable during the contract period or in case may be fixed by the Board for few or entire post.

3.4.86 The contractor should ensure payment of wages to his workmen on or before 7th of every succeeding month. The payment of wages will be made in the presence of an authorized representative of Board at a place and time notified for the purpose.

3.4.87 The wages shall be paid to workmen without any deduction except those under the payment of Wages Act and Minimum wages Act.

3.4.88 The Contractor should ensure that his workmen are granted Holidays/Leave with wages as applicable to the daily wages employee as per relevant Act/Rules.

3.4.89 The Cantonment Board Chakrata reserves its rights to withhold bills, if the contractor fails to produce proof for having remitted the ESI/PF dues.

3.4.90 The contractor must get police verification of all his personnel employed at Cantonment Board Chakrata and submit the report to this office along with voter IDs, and other valid proof of residence and qualifications. The Contractor has to submit the attested photocopies of his voter ID, PAN, residential address, educational qualifications etc.



3.4.91 If any of the personnel of the contractor indulges in theft or any illegal/irregular activities, misconduct, the contractor will take appropriate action as per law and rules against its erring personnel in consultation with this office and intimate the action taken to this office. Such personnel, who indulge in such type of activities, should not be further employed in this office by the contractor in any case.

3.4.92 Whenever there is a duplication of clause either in the terms and conditions or in the agreement, the clause which is beneficial to the Cantonment Board Chakrata will be considered applicable at the time of any dispute/following any statutory rules.

3.4.93 The contractor shall appoint at least one Supervisor on his behalf to coordinate with Board and supervise the work done by the personnel deployed to the satisfaction of Cantonment Board Chakrata. The details of the Supervisor shall be provided separately to the Cantonment Board Chakrata before commencement of the work and any change shall also be duly intimated.

3.4.94 The contractor shall ensure that there is no scope for any grievance from the personnel deployed by him on account of delayed payment of wages.

3.4.95 No advance payment will be made. Payment will be made on monthly basis after satisfactory completion of work.

3.4.96 In case of any complaint of non-fulfilment of any obligation under the contract, the CEO, Cantonment Board Chakrata reserves the right to deduct the payments due from the contractor from monthly bill (s)

3.4.97 Proof of challan/ receipt for the payment made towards wages to each employee should be furnished to this office along with the monthly charges bill to be submitted for reimbursement. In case this office receives any complaint regarding non-payment of wages to any personnel the amount payable to these personnel will be recovered from contractor's bill and paid to such personnel. iv) The contractor shall strictly comply with the provisions of the Employee Provident Fund Act, 1952 and the provisions of Employees' State Insurance Act, 1952. The contractor shall deposit Employees and Employer Contributions in the designated account with the designated authority every month. The contractor shall furnish along with each running bill, the challan / receipt for the payment of Provident Fund and ESI made on account of the workers for the preceding month together with their ESIC Ins. No. / EPF subscriber number.

3.4.98 The Cantonment Board Chakrata shall pay to the contractor only the minimum wages, as per the contract, on monthly basis and any other payments such as PF/ESI/Service Tax etc. would be made only after submission of proof of payment by the contractor to the concerned statutory authorities/accounts. The other payment like bonus, performance bonus will not make to outsourced employees.

*Signature*

*Signature*



3.4.99 TENDER WILL BE AWARDED AS PER PUBLIC PROCUREMENT (PREFERENCE TO MAKE IN INDIA) ORDER 2017 AND ITS AMENDMENT.

3.4.100 All tender awarded as per Govt. of India MSME preference instructions and its amendment time to time.

\*\*\*\*\*

**Note: These terms and conditions are part of the Contract/Agreement as indicated in the Agreement between Cantonment Board Chakrata and the Agency and any non-compliance shall be deemed as breach of the Contract/Agreement.**



**(R.N. Mandal)**

Chief Executive Officer  
Cantonment Board Chakrata



**Bid Document/ बिड दस्तावेज़**

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	19-08-2024 16:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	19-08-2024 16:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	30 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Defence
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Defence
Organisation Name/संगठन का नाम	Dg Of Defence Estate
Office Name/कार्यालय का नाम	*****
Item Category/मद केटेगरी	Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Assistant Teacher Primary; Assistant Teacher Primary; Graduate , Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Assistant Teacher High School; Assistant Teacher High School; Graduate , Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Lecturer Intermediate Teacher; Lecturer Intermediate Teacher; Post Graduate
Contract Period/अनुबंध अवधि	1 Year(s)
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का)	40 Lakh (s)
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	3 Year (s)
Past Experience of Similar Services required/इसी तरह की सेवाओं का पिछला आवश्यक अनुभव है	Yes
MSE Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट/ and Turnover/टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है	Yes
Startup Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट/ and Turnover/ टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है	Yes



Bid Details/बिड विवरण	
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Estimated Bid Value/अनुमानित बिड मूल्य	4799182.19
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation

#### EMD Detail/ईएमडी विवरण

Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक	State Bank of India
EMD Amount/ईएमडी राशि	100000

#### ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

#### Beneficiary/लाभार्थी :

Chief Executive Officer Cantonment Board Chakrata  
Cantonment Board Chakrata, Department of Defence, DG of Defence Estate, Ministry of Defence  
(Chief Executive Officer)

#### Splitting/विभाजन

Bid splitting not applied/बोली विभाजन लागू नहीं किया गया.

#### MII Compliance/एमआईआई अनुपालन

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन	Yes
-------------------------------	-----

#### **MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता**

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
4. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
5. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.
6. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.
7. Past Experience of Similar Services: The bidder must have successfully executed/completed similar Services over the last three years i.e. the current financial year and the last three financial years(ending month of March prior to the bid opening): -
  1. Three similar completed services costing not less than the amount equal to 40% (forty percent) of the estimated cost; or
  2. Two similar completed services costing not less than the amount equal to 50% (fifty percent) of the estimated cost; or



3. One similar completed service costing not less than the amount equal to 80% (eighty percent) of the estimated cost.

**Additional Qualification/Data Required/अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा**

**The Bidder should have executed at least X No. projects with contract value not less than (Rs) yy for each contract of providing manpower services to Central/ State Government Departments/ Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies in last N financial years:As per Tender Document.**

**The Bidder should have executed at least X No. projects with supply of xx..no. of manpower in each contract of providing manpower services to Central/ State Government Departments/ Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies in last N financial years:As per Tender Document.**

**Geographic Presence: Office registration certificate:As per Tender Document.**

**Scope of work & Job Description:**[1722073034.pdf](#)

**In case, the buyer wants to retain some of the existing resources then buyer is needed to upload the list of resources along with the quantity of each type or resource to be continued by the successful bidder/service provider under the new contract as per the T&C of new contract concluded on the basis of this bid along with approval of Competent Authority.:[1722073037.pdf](#)**

**Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Assistant Teacher Primary; Assistant Teacher Primary; Graduate ( 7 )**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification	Values
<b>Core</b>	
Type of Function	Assistant Teacher Primary
List of Profiles	Assistant Teacher Primary
Educational Qualification	Graduate
Specialization	DELED or BED
Post Graduation	Not Required
Specialization for PG	Not Applicable
Experience	0 to 3 Years
State	NA
District	NA
Zipcode	NA
<b>Addon(s)/एडऑन</b>	
<b>Additional Details/अतिरिक्त विवरण</b>	
Title for Optional Allowance 1	0
Title for Optional Allowance 2	0
Title for Optional Allowance 3	0
Designation	Assistant Teacher Primary

**Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़****Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	*****	*****Dehradun	7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Basic monthly pay (INR) exclusive of GST : 15000</li><li>• Bonus (INR Monthly) : 0</li><li>• EDLI (INR Monthly) : 0</li><li>• EPF Admin Charges (INR Monthly) : 0</li><li>• Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0</li><li>• Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc &amp; excluding GST) : 0</li><li>• Optional Allowances 1 (INR Monthly) : 0</li><li>• Optional Allowances 2 (INR Monthly) : 0</li><li>• Optional Allowances 3 (INR Monthly) : 0</li><li>• Provident Fund (INR Monthly) : 1950</li><li>• ESI (INR Monthly) : 487</li><li>• Tenure/ Duration of Employment (In Months) : 12</li></ul>

**Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Assistant Teacher High School; Assistant Teacher High School; Graduate ( 5 )****Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification	Values
Core	



Specification	Values
Type of Function	Assistant Teacher High School
List of Profiles	Assistant Teacher High School
Educational Qualification	Graduate
Specialization	Bed
Post Graduation	Optional
Specialization for PG	As per Subject and Govt Order
Experience	0 to 3 Years
State	NA
District	NA
Zipcode	NA
<b>Addon(s)/एडऑन</b>	
<b>Additional Details/अतिरिक्त विवरण</b>	
Title for Optional Allowance 1	0
Title for Optional Allowance 2	0
Title for Optional Allowance 3	0
Designation	Assistant Teacher High School

**Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़**

**Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी**

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
----------------	---	-------------	---------------------------------	--

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	*****	*****DEHRADUN	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basic monthly pay (INR) exclusive of GST : 16000</li> <li>• Bonus (INR Monthly) : 0</li> <li>• EDLI (INR Monthly) : 0</li> <li>• EPF Admin Charges (INR Monthly) : 0</li> <li>• Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0</li> <li>• Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc &amp; excluding GST) : 0</li> <li>• Optional Allowances 1 (INR Monthly) : 0</li> <li>• Optional Allowances 2 (INR Monthly) : 0</li> <li>• Optional Allowances 3 (INR Monthly) : 0</li> <li>• Provident Fund (INR Monthly) : 2080</li> <li>• ESI (INR Monthly) : 520</li> <li>• Tenure/ Duration of Employment (In Months) : 12</li> </ul>

**Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Lecturer Intermediate Teacher; Lecturer Intermediate Teacher; Post Graduate ( 5 )**

**Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**

Specification	Values
<b>Core</b>	
Type of Function	Lecturer Intermediate Teacher
List of Profiles	Lecturer Intermediate Teacher
Educational Qualification	Post Graduate
Specialization	BED



Specification	Values
Post Graduation	Required
Specialization for PG	As per subject and Govt Order
Experience	0 to 3 Years
State	NA
District	NA
Zipcode	NA
<b>Addon(s)/एडऑन</b>	
<b>Additional Details/अतिरिक्त विवरण</b>	
Title for Optional Allowance 1	0
Title for Optional Allowance 2	0
Title for Optional Allowance 3	0
Designation	Lecturer Intermediate Teacher

#### Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़

#### Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
----------------	---	-------------	---------------------------------	--

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	*****	*****DEHRADUN	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basic monthly pay (INR) exclusive of GST : 18000</li> <li>• Bonus (INR Monthly) : 0</li> <li>• EDLI (INR Monthly) : 0</li> <li>• EPF Admin Charges (INR Monthly) : 0</li> <li>• Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0</li> <li>• Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc &amp; excluding GST) : 0</li> <li>• Optional Allowances 1 (INR Monthly) : 0</li> <li>• Optional Allowances 2 (INR Monthly) : 0</li> <li>• Optional Allowances 3 (INR Monthly) : 0</li> <li>• Provident Fund (INR Monthly) : 2340</li> <li>• ESI (INR Monthly) : 585</li> <li>• Tenure/ Duration of Employment (In Months) : 12</li> </ul>

## Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

### 1. Generic

OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

### 2. Purchase Preference (Centre)

Bid reserved for Make In India products: Procurement under this bid is reserved for purchase from Class 1 local suppliers as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific



Goods/Products. The minimum local content to qualify as a class 1 local supplier is denoted in the bid document 50%. All bidders must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which the bid is liable to be rejected. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020 . In case Buyer has selected Purchase preference to Micro and Small Enterprises clause in the bid, the same will get precedence over this clause.

### **3. Purchase Preference (Centre)**

Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for percentage of 100% of total value.

### **4. Purchase Preference (Centre)**

Preference to Make In India products (For bids less than 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document 50%. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. In case Buyer has selected Purchase preference to Micro and Small Enterprises clause in the bid, the same will get precedence over this clause.

### **5. Purchase Preference (Centre)**

Preference to Make In India products (for bids greater than 200 Crore) (can also be used in Bids less than 200 Crore but only after exemption by competent authority as defined in Deptt of Expenditure OM dated 28.5.2020): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document 50%. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. In case Buyer has selected Purchase preference to Micro and Small Enterprises clause in the bid, the same will get precedence over this clause.

### **6. Purchase Preference (Centre)**

Procurement under this bid is reserved for purchase from Micro and Small Enterprises whose credentials are validated online through Udyog Aadhaar/URC for that product/service category. If the bidder wants to avail the reservation benefit, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small

Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service.

## Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the [General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें](#), conditions stipulated in Bid and [Service Level Agreement](#) specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action

in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी



गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

**---Thank You/धन्यवाद---**